SPECIAL MENTIONS

Demand for implementation of Justice Usha Mehra Commission's recommendations regarding policing in public transport

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Nirbhaya's incident which happened in a transport bus was hardly forgotten by the people and another incident of rape in a cab has shaken the nation. Report on post-Nirbhaya's Commission to zero in on lapses in transport and policing, headed by Justice Usha Mehra is available and has remained unimplemented. Sir, I would like to urge the Government through this august House that Government should examine and ensure implementation of policing in public transport.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. Shri A.K. Selvaraj, not present; Shri Avinash Pande, not present; Prof. Jogen Chowdhury, not present; Shri Ahamed Hassan, not present; Shrimati Kanak Lata Singh.

Demand for restoring old system of monitoring standards of ITIs without imposing any fee on students in the country

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, केन्द्रीय सरकार के मुखिया बार-बार कहते सुने गए हैं कि कौशल विकास पर कार्य करना होगा। इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI's) करती रही हैं और नौजवानों की विभिन्न ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर वगैरह के काम से निपुण बनाती रही है।

महोदय, ITI's के सभी मानकों को सितम्बर 2012 से पहले केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा पूरा करवाया जाता था, जिसके एवज में नाममात्र का चार्ज लिया जाता था। कुछ राज्य 7,500 रुपये वसूलते थे और कुछ राज्य तो मानकों और जांच पड़ताल को पूरा करवाने के लिए निःशुल्क तरीके से ITIs के संचालनकर्ता संस्थाओं से पूर्ण करवा लेते थे। सितम्बर 2012 से इस कार्य की एवज में गुणवत्ता लाने के नाम पर 65,000 रुपया वसूला जा रहा है, क्योंकि इस कार्य को तीन निजी औद्योगिक संघों को दे दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो विद्यार्थी ITIs के किसी भी ट्रेड में दाखिला लेते हैं, तो उनसे भारी-भरकम रकम वसूली जाती है, क्योंकि बिना विद्यार्थियों से रकम वसूले इन संघों द्वारा थोपे गए 65,000 रुपये को कोई भी ITIs संचालनकर्ता संस्थाएं देने की स्थिति में नहीं है। मजे की बात यह है कि बिना राज्यों की सहमति के यह कार्य राज्यों से छीन लिया गया है, जिसे राज्य निःशुल्क करते थे। आर्थिक दबाव में आकर विद्यार्थी ITI's संस्थानों में कम दाखिला ले रहे हैं।

इस कार्य को करने वाली तीनों संस्थाएं गुणवत्ता सुधारने के नाम पर अपना आर्थिक लक्ष्य सुधार रही हैं। मेरी मांग है कि इस पर थोपी गई राशि को अविलम्ब वापस लेना चाहिए और पूर्व की भांति ITIs का संचालन सरकार स्वयं सुनिश्चित करवाए, जिससे विद्यार्थियों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव न पड़े। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : सर, मैं इनके विशेष उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

†[شری محمد علی خان (آندھراپردیش) : سر، میں ان کے وشیش الّیکھ سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔]

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी इनके विशेष उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं भी इनके विशेष उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

†[چودھری منور سلیم (اترپردیش) : سر، میں بھی ان کے وشیش الیکھ سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔ (ختم شد)]

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Shri Vijay Jawaharlal Darda, not present; Shri Mansukh L. Mandaviya, not present; Shri Parimal Nathwani, not present; Shri Motilal Vora, not present; Shri Vivek Gupta, not present; Shri A.U. Singh Deo, not present; Shri K.R. Arjunan, not present.

The House stands adjourned to meet on Monday, the 15th December, 2014 at 1100 hours.

The House then adjourned at eight minutes past five of the clock
till eleven of the clock on Monday, the
15th December, 2014.

†Transliteration in Urdu Script.